पत्र सं0– वि०प्रा० (II) य[1] –2/2010–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा में नवनिर्मित दो अदद बालक छात्रावास (प्रति 150 शय्या) के लिए आवश्यक उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु स्वीकृत राशि रू० 85,80,000=00 (पचासी लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2018–19 में संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3097, दिनांक 28.12.2017 के द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा में नवनिर्मित दो अदद बालक छात्रावास (प्रति 150 शय्या) के लिए आवश्यक उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु रू० 85,80,000=00 (पचासी लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परंतु, संस्थान द्वारा उक्त विमुक्त कुल राशि प्रत्यर्पित कर दी गई।

2. राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा के पत्रांक–387, दिनांक 12.09.2018 द्वारा की गई मांग के आलोक में उक्त प्रत्यर्पित राशि राशि रू० 85,80,000=00 (पचासी लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2018–19 में संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

3. विमुक्ति उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0109–पोलिटेकनिक (निश्चय)" के अधीन 52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021040109 है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

5. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, मढ़ौरा से की जायेगी।

6. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक एवं आवश्यकता से अधिक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।

8. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि०, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) य[1] –2/2010– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) य[1] –2/2010– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, मढ़ौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) य[1] –2/2010– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) य[1] –2/2010– 909 /पटना, दिनांक– 12-3-019

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.03.19
सरकार के उप सचिव